

डिजिटल इंडिया

डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सरकार की सेवाएँ नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन अवसंरचना में सुधार करके और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाकर या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाकर उपलब्ध कराई जाए। [१] 2] इस पहल में ग्रामीण क्षेत्रों को हाई-स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने की योजना शामिल है। डिजिटल इंडिया में तीन मुख्य घटक होते हैं: सुरक्षित और स्थिर डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास, सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से वितरित करना, और सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता।

डिजिटल इंडिया की पहल

भारत सरकार की इकाई भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) जो भारतनेट परियोजना का संचालन करती है, डिजिटल इंडिया (डीआई) परियोजना की संरक्षक है। [९] [१०]

कार्यान्वयन

नई डिजिटल सेवाएं

इस पहल के माध्यम से दी जाने वाली कुछ सुविधाएं भारत नेट, डिजिटल लॉकर, ई-शिक्षा, ई-स्वास्थ्य, ई-साइन, ई-शॉपिंग और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल हैं। डिजिटल इंडिया के हिस्से के रूप में, भारत सरकार ने बोटनेट सफाई केंद्र शुरू करने की योजना बनाई है। [११]

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का उद्देश्य सभी फ्रंट-एंड सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन लाना है।

MyGov.in नीति और शासन के मामलों पर जानकारी और विचार साझा करने का एक मंच है। [१२] यह "चर्चा", "करो" और "दुष्प्रचार" दृष्टिकोण के माध्यम से शासन में नागरिक जुड़ाव का एक मंच है। [७]

UMANG (यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस) एक सरकार है भारत में सभी में एक एकीकृत सुरक्षित मल्टी-चैनल मल्टी-प्लेटफॉर्म मल्टी-लिंगुअल मल्टी-सर्विस फ्रीवेयर मोबाइल ऐप है जो 1,200 से अधिक केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं के लिए एंड्रॉइड, आईओएस, विंडोज और यूएसएसडी (फीचर फोन) पर कई भारतीय भाषाओं में एक्सेस कर रहा है।

AADHAR, DigiLocker, Bharat Bill Payment System, PAN, EPFO सेवाओं, PMKVY सेवाओं, AICTE, CBSE, कर और शुल्क या उपयोगिताओं बिल भुगतान, शिक्षा, नौकरी खोज, कर, व्यवसाय, स्वास्थ्य, कृषि, यात्रा जैसी सेवाओं सहित भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग, जन्म प्रमाण पत्र, ई-जिला, ई-पंचायत, पुलिस निकासी, पासपोर्ट, निजी कंपनियों से अन्य उपयोगिता सेवाएं और भी बहुत कुछ। [१३]

eSign फ्रेमवर्क नागरिकों को आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके ऑनलाइन एक दस्तावेज़ पर डिजिटल हस्ताक्षर करने की अनुमति देता है। [citizens]

स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) मोबाइल ऐप का उपयोग लोगों और सरकारी संगठनों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है।

eHospital आवेदन महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है जैसे ऑनलाइन पंजीकरण, शुल्क का भुगतान और नियुक्ति, ऑनलाइन नैदानिक रिपोर्ट, ऑनलाइन रक्त की उपलब्धता की पूछताछ करना आदि।

डिजिटल उपस्थिति: पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 [5] को एक वास्तविक समय के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखने के लिए attendance.gov.in को लॉन्च किया गया था।

[१४] यह पहल दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में एक सामान्य बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली (बीएस) के कार्यान्वयन के साथ शुरू हुई।

[१५]

बैंक-एंड डिजिटाइजेशन

काले धन का उन्मूलन: भारत के 2016 के केंद्रीय बजट में 11 प्रौद्योगिकी पहल की घोषणा की गई, जिसमें डेटा चोरों को नाब टैक्स चोरों के लिए उपयोग करना शामिल है, आईटी कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर पैदा करना होगा जो कि आवश्यक प्रणालियों का निर्माण करेगा। [16]

डिजिटल साक्षरता मिशन में छह करोड़ ग्रामीण परिवार शामिल होंगे। [१६]

इसे देश के 550 किसान बाजारों को प्रौद्योगिकी के उपयोग से जोड़ने की योजना है। [१ 550]